गरीबी घटने के दौर में मुफ्त राशन का हकदार कौन?



गरीबी में कमी आने के बावजूद भारत में वर्ष 2022-23 के आंकड़ों में छह करोड़ परिवार ऐसे हैं, जिनका नियमित खर्च उनकी आय से अधिक है। ऐसे में सवाल यह है कि मुफ्त राशन का लाभ किन परिवारों को मिलना चाहिए? लेखक के अनुसार, खाद्य सहायता का सबसे मजबूत आधार उन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बनाना चाहिए, जिनके लिए रोजमर्रा की आवश्यक जरूरतें पूरी करना भी चुनौती है।

आर्थिक विकास और गरीबी के आंकड़ों से आगे की वास्तविकता -

- देश की GDP वृद्धि और गरीबी के आंकड़े आर्थिक प्रगति का संकेत देते हैं, लेकिन आम परिवारों की वास्तविक आर्थिक स्थिति को पूरी तरह नहीं दर्शाते।
- देश में लाखों परिवार ऐसे हैं, जिन्हें यह चिंता रहती है कि उनकी आय से भोजन, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी हो पाएंगी या नहीं।
- एक सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2022-23 में लगभग 19.8% परिवारों का नियमित खर्च उनकी सालाना आय से अधिक था।
- यह आंकड़ा 2020-21 के 30.4% की तुलना में कम है, लेकिन 2015-16 के 11.3% से काफी अधिक है।
- इसका अर्थ है कि आर्थिक स्थिति में सुधार के बावजूद परिवारों पर वित्तीय दबाव बना हुआ है।

क्या खर्च आय से अधिक होना गरीबी का प्रमाण है?

- जिन परिवारों का खर्च उनकी आय से अधिक है, जरूरी नहीं कि वे सभी गरीब या आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हों।
- कुछ परिवार अपनी बचत से खर्च पूरा कर सकते हैं।
- कुछ परिवारों की आय मौसमी होती है, जैसे कृषि क्षेत्र में काम करने वाले परिवार।
- कुछ परिवार भविष्य में मिलने वाली आय के आधार पर अस्थायी कर्ज लेते हैं।
- इसलिए केवल आय और खर्च के बीच अंतर के आधार पर सरकारी सहायता का पात्र निर्धारित करना उचित नहीं है।
- सरकार को यह पहचानना होगा कि किन परिवारों के पास आर्थिक संकट से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन और बचत नहीं है।

आर्थिक रूप से कमजोर 40% परिवारों की स्थिति -

- लेखक के अनुसार, आर्थिक संकट की वास्तविक पहचान के लिए देश के सबसे निचले 40% आय वाले परिवारों की स्थिति का अध्ययन करना जरूरी है।
- वर्ष 2022-23 के सर्वेक्षण के अनुसार इन परिवारों की औसत मासिक आय लगभग 11,800 रुपये थी। इनका नियमित मासिक खर्च लगभग 10,500 रुपये था। इसके बावजूद लगभग 29% परिवार अपनी आय से अधिक खर्च कर रहे थे।
- ऐसे परिवारों की कुल संख्या लगभग 3.4 करोड़ थी।
- ये सभी आर्थिक दबाव झेलने वाले परिवारों का लगभग 60% हिस्सा थे।
- इन परिवारों की समस्या केवल आय और खर्च के बीच अंतर नहीं है, बल्कि उनकी सीमित आर्थिक क्षमता भी है।
- इनके पास बचत और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन कम होते हैं। इसलिए अचानक आने वाला खर्च इनके लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है।

लेखक के अनुसार, मुफ्त राशन का सबसे मजबूत दावा उन परिवारों का है, जिनकी आय कम है, और जिनके पास आर्थिक संकट से निपटने के लिए पर्याप्त बचत नहीं है।

- विशेष रूप से निचले 40% आय वर्ग के परिवारों पर ध्यान देना चाहिए।
- हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि इस वर्ग के सभी परिवार आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हैं।

- इसी प्रकार, इससे ऊपर के आय वर्ग के सभी परिवारों को आर्थिक रूप से सुरक्षित भी नहीं माना जा सकता।
- इसलिए राशन की पात्रता तय करते समय गरीबी के पारंपरिक आंकड़ों के साथ-साथ परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति का भी मूल्यांकन होना चाहिए।
- केवल इस आधार पर कि किसी परिवार का खर्च आय से अधिक है, उसे मुफ्त राशन का पात्र नहीं माना जाना चाहिए।

सरकारी सहायता को प्रभावी बनाने की जरूरत -

लेखक के अनुसार, सरकार के सामने चुनौती खाद्य सब्सिडी को बढ़ाना या घटाना नहीं, बल्कि उसे सही लाभार्थियों तक पहुंचाना है।

इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं :

- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पहचान की जाए।
- केवल वार्षिक आय नहीं, बल्कि परिवार को नियमित रूप से आय प्राप्त होती है या नहीं, इसका भी अध्ययन किया जाए।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और भोजन पर होने वाले अनिवार्य खर्चों को ध्यान में रखा जाए।
- यह देखा जाए कि क्या परिवार रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज लेने को मजबूर हैं।
- मुफ्त राशन से परिवारों के पोषण स्तर और खाद्य उपभोग पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए।
- यह पता लगाया जाए कि खाद्यान्न सहायता से परिवारों को आर्थिक संकट के दौरान कितनी राहत मिल रही है।

मुफ्त राशन का उद्देश्य केवल गरीबी के आंकड़ों के आधार पर सहायता देना नहीं, बल्कि उन परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिए, जिनकी सीमित आय और कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण भोजन जैसी बुनियादी जरूरतें भी प्रभावित हो सकती हैं।

इसलिए सरकारी सहायता की पात्रता तय करने में आय, खर्च, रोजगार की स्थिरता, बचत और परिवार की जरूरतों को शामिल करना आवश्यक है।

'द हिंदू' में प्रकाशित राजेश शुक्ला के लेख पर आधारित। 11/11/26